Number of brandies of Nationalised Banks in Maharashtra

*170. SHRI VISHWASRAO RAMRAO PATIL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what fe the number of branches of nationalised Banks working in Maharashtra at present;

(b) what is the number of branches, out of them, that are working in rural areas; and

(c) what is the number of branches opened and proposed to be opened in the State d.iring 1990-91?

THE FINANCE MINISTER (SHRI YASHWANT SINHA): (a) 4409 branches of Public Sector Banks existed as on 30th June, 1990,

(b) 1792 out of (a) above.

(c) RBI has reported that 53 branches were opened in Maharashtra during the year 1990, and 55 licences are pending as on 26.2.1991 in respect of rural and semi-urban centres in Maharashtra.

खाद्य पदार्थों का निर्यात

*171. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्री बलराम सिंह यादव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश से भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का निर्यात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने रुपए मूल्य के खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया है ;

(ग) चालू वर्ष में खाद्य पदार्थों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी-मुद्रा के प्राप्त होने की संभावना है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय खाद्य पदार्थों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री, साथ ही में विधि और याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री सुब्रह मण्यम स्वामी): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों (तीय') के दौरान संसाधित खाद्य उत्पादों के निर्यात आंकड़े तथा चालू वर्ष के लिए निर्यात के अनुमानित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

(मूल्य लाख रुपए में)

1987–88	29416
1988–89	28963
1989–90	32035
1990–91 (अनुमान)	33500

(घ) जी हां । भारतीय संसाधित खाद्य उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका और ई.ई.सी. जैसे विकसित देशों में कीमत, क्वालिटी और पैकेजिंग क्षेत्रों में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है ।

(ङ) संसाधित खाद्य का निर्यात बढ़ाने के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता, शुल्क वापसी, आयात प्रतिपूर्ति, लाइसेंस, पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर रियायती आयात शुल्क, अग्रिम लाइसेंस आदि जैसे प्रोत्साहन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में व्यापार प्रतिनिधिमण्डल भेजने तथा उनमें भाग लेने के लिए सहायता सरकार द्वारा पहले से ही दी जा रही है ।

विश्व के बाजार में खाद्य-प्रसंस्करण उद्योग द्वारा प्रतिस्पर्धा का सामना

*172. **श्री अजीत जोगी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पर आधारित औद्योगिक उत्पादों के समर्थन मूल्यों में की गई अत्यधिक वृद्धि से खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप खाद्य-प्रसंस्करण उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो इन वस्तुओं को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

वस्त्र तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्री हुकुमदेव नारायण यादव): (क) कृषि पर आधारित औद्योगिक उत्पादों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने की कोई नीति नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

Extension of textile workers rehabilitation fund scheme to the state of Gujarat

*173. SHRI VITHALBHAI M. PATEL:
SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gujarat Government has made a request for the extension of Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme in case of partially closed textile mills.

(b) if so, what action the Central Government have taken so far in this regard; and

(c) whether Central Government have taken any action on the request of the State Government for the relaxation of the guidelines of Reserve Bank of India for lending assistance to new managements which are willing to re-open closed textile mills?

THE MINISTER OF TEXTILES AND FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI HUKUMDEo NARAYAN YA-DAV): (a) Yes, Sir.

It has not been possible to extend the scheme to partially closed mills due to funds constraints.

The proposal of the Government of Gujarat for relaxation of norms for grant of working capital to sick textile units was discussed in a meeting held by Secretary, Textiles, with representatives of Department of Banking, Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India and the Government of Gujarat. While gene ral relaxation of the norms was not agreed to, the representatives of Reserve Bank of India and Industrial Development Bank of India agreed to consider relaxation of guidelines on a case to case basis, upon merits.

Cases pending in the Shillong Bench of the Guwahati High Court

*174. SHRI G. G. SWELL: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state;

(a)whether the Bench of the Guwahati High Court at Shillong has not been functioning satisfactorily as a result of which the people of Shillong and Meghalaya have to approach Guwahati High Court proper;

(b)what is the number of cases from Meghalaya pending before the Guwahati High Court proper;

what is the number of sittings that » the Shillong Bench had in the last one year and the total duration thereof;

whether Meghalaya Government has been representing for the setting up of a full-fledged High Court at Shillong and has made land available for the purpose; and